medium irrigation projects in the country during the Seventh Five Year Plan and during 1990-91, 1991-92 and 1992-93, the disbursements of external assistance were as follows:-

Seventh Five Year Plan—US $ 1211.22 million.

1990-91 . . . US $ 238.05 million

1991-92 . . . US $ 275.59 million

1992-93 . . . US $ 215.10 million

(b) to (d) As regards utilisation of assistance, there have been some instances of under utilisation of the external assistance in some projects. The main reasons for this are:—

(i) Initial slippage in the implementation of the project.

(ii) Delay in declaring loan/credit effectiveness by the World Bank on account of satisfactory action plan on resettlement and rehabilitation.

(iii) Delay in approval of Local Competitive Bidding and International Competitive Bidding packages by the World Bank.

(iv) State Government's financial crunch.

(v) Untimely release of allotted funds to the projects.

(vi) Subsequent cut in annual plan tion of the project.

(vii) Delay in finalisation of model bidding documents.

(viii) Imposition of certain conditions viz. carrying out studies etc. by the World Bank during the course of implementation of the project.

(ix) Ban on procurement imposed by the World Bank.

(x) Natural calamities.

(xi) Appreciation of donor currencies in terms of rupees.

Setting up of pulichintala project in A.P.

1205. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Andhra Pradesh has submitted a proposal for constitution of Pulichintala Project; and

(b) if so, at what stage of consideration is the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The modified report on Pulichintala Project at an estimated cost of Rs. 269 crores has been received in July, 1993. After examination Central Water Commission has communicated observations on irrigation planning and foundation engineering to the State Govt. The State Government is required to comply with the observations of the Central Water Commission.

बिहार में कुट्कू (मंडल) बांध का निर्माण

1206. **श्री ब्रह्म देव आनन्द पासवान :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले में स्थित कुटकू (मंडल) बांध के निर्माण के मामले में पर्यावरण की दृष्टि से अनिवार्य आठ शर्तों का पालन किया गया है;

(ख) क्या उक्त बांध के निर्माण में 20,000 एकड़ में फैला सघन जंगल बांध में डूब रहा है;

(ग) क्या बांध में गाद के जमाव तथा भूक्षरण को रोकने के लिए उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या कुट्कू बांध में डूबे 27 गांवों के विस्थापित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ङ) क्या पलामू बांध परियोजना को बचाने के लिए कोई उपाय किये गये हैं;

(च) क्या विस्थापित लोगों को मुआवजा देने के स्थान पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है; और

(छ) यदि उपर उल्लिखित भागों का उत्तर "हां" में है तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गयी स्वीकृति में निर्धारित किए गए सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध समिति गठित की है।

(ख) यह अनुमान है कि पूर्ण जलाशय स्तर पर लगभग 19,000 एकड़ वन भूमि जल मग्नता के अन्तर्गत आती है। स्वीकृत निबंधनों के अनुसार समतुल्य गैर वन भूमि पर वन रोपण करने के लिए इस परियोजना के प्राक्कलन में 17.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) अनुप्रयोज्य भंडारण, जिसकी जलाशय में व्यवस्था है, जलाशय में गाद के आने को रोकता है। इसके अतिरिक्त, स्पिलवे भाग में निम्न स्तर पर दो पानी साफ करने के स्लूस लगाए गए हैं। बांध के प्रतिप्रवाह जलग्रहण क्षेत्र से बाद के कटाव को रोकने के लिए 31.21 करोड़ रुपए (1985 गतर) की अनुमानित लागत पर 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने हेतु जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाएं भी तैयार की गयी हैं।

(घ), (च) और (छ) 27 प्रभावित गांवों में से 20 जलमग्न क्षेत्र में आते हैं। 15 गांवों में भूमिअधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। एक गांव जलमग्न नहीं होता है जबकि दूसर गांव में कोई आबादी नहीं है। शेष 3 गांवों में स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

(ङ) जी हां, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गयी स्वीकृति में पलामू टाइगर परियोजना की सुरक्षा के उपायों का उल्लेख है।

1207. [21 दिसम्बर 1993 के लिए स्थानान्तरित।]

Water level in Uttar Pradesh and Haryana

1208. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the water level in the States of Uttar Pradesh and Haryana has considerably gone down and if so, what are the reasons thereof; and

(b) whether it is also a fact that Tubewells, which were sunk about five years back, have become inoperative and if so whether Government propose to provide subsidy to the farmers on that behalf and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. Decline of more than 2 metres in the ground water level has been observed in certain localised pockets of Haryana and Uttar Pradesh. Fall in ground water level is attributed to variation in amount and distribution of rainfall and intensive development of ground water.

(b) The information available with the Agriculture Department of Government of Haryana and Minor Irrigation Department of Govt. of Uttar Pradesh does not show that the tubewells sunk about five years back have become inoperative due to decline in water table. There is no proposal to provide subsidy to the farmers on this account.